ग्राहक 1.5 सिलिंडर उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए रखा जाता है।

30.6.95 की स्थिति के अनुसार तेल कंपनियों द्वारा एकत्रित जमाराशि करीब 1700 करोड़ रुपए थी।

(ख) : जी, नहीं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता

403. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षा परिषद् में भारत को स्थायी सदस्य बनाये जाने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रयास हो रहे हैं;

(ख) किन-किन देशों ने इस पहल में भारत का साथ दिया है; और

(ग) वर्तमान समय में कौन-कौन से देश सुरक्षा परिषद् के सदस्य हैं तथा सदस्यता का निर्धारण किस प्रकार होता है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) भारत ने यह कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों के रूप में अपने सेवाएं देने के लिए तैयार है। सरकार अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाने हेतु सभी आवश्यक प्रयास कर रही है।

(ख) और (ग): इस समय अमरीका, यू०के०, फ्रांस, रूसी परिसंघ और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23(1) द्वारा स्थायी सदस्यता दी गई थी।

नए सदस्यों को सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करना होगा और संयुक्त राष्ट्र महासभा के दो तिहाई बहुमत से इसका अनुमोदन किया जाना होगा, तथा इसके लिए पांच स्थायी सदस्यों के सहमति मत की भी आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने "सुरक्षा परिषद् में औचित्य पूर्ण प्रतिनिधित्व और इसकी सदस्य संख्या में बढ़ोत्तरी के प्रश्न" पर एक मुक्त कार्यदल नियुक्त किया है। इस समय यह कार्यदल किसी देश विशेष की उम्मीदवारी पर विचार नहीं कर रहा है।

Scaling the Dried wells by ONGC at sibsagar

404. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pelased to state:

(a) whether it is a fact that in the district of Sibsagar ONGC did not take proper care to seal the dried wells by filling up the same with sand so as to save the land from seismic eruption and damage caused annually by floods etc.;

(b) whether Government are also aware that it is causing a serious concern in view of the downward turn of the river Brahmaputra towards South and it is situated in regions more prone to earthquake; and

(c) if so, what are the details thereof and what action has been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) to (c) No, Sir. In ONGC, the dried wells are abandoned by sealing the wells properly following a standard procedure in compliance with the provisions of Oil Mines regulation, 1984. The procedure followed in abandoning dried wells ensures that the abandoned wells do not pose any problem even under influence of extraneous factors like flood etc.

Loss to forest wealth in hilly districts of U.P. by forest

405 SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:
DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the district-wise estimated loss to forest wealth in the hill districts of U.P. by forest fires in May-June 1995;

(b) the reasosn for the wide spread fire and steps that were taken in control the same;

(c) whether it is a fact that the fires were deliberate and the timber contractors were behind the same and if so, what are the facts thereof; and

(d) whether it is a fact that forest fire fighting facilities are not available and where available were not used and if so, what is the factual positin?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) to (d) The information is being collected from the state government and will be laid on the table of the House.

उत्तर भारत में डीजल, पेट्रोल की कमी

406. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर उत्तर भारत में अभी भी डीजल अथवा पेट्रोल की कमी चल रही है,

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण है, और

(ग) हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर को मई, जून में तथा 15 जुलाई तक डीजल का कितना-कितना कोटा प्रदान किया गया और उनकी मांग कितनी-कितनी थी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, मार्च-अप्रैल, 1995 में मथुरा रिफाइनरी की अनियोजित बंदी, बंदरगाहों और रेलवे ढुलाई में संख्यानात्मक बाधाओं के कारण पिछले महीनों के दौरान पेट्रोल और डीजल की कुछ कमी हो गई थी। तथापि, वैकल्पिक स्त्रोतों और सड़क मार्ग से उत्पाद की व्यवस्था करके आवश्यक मांग पूरी की गई।

(ग) डीजल एक निश्चित उत्पाद नहीं है और पूरे देश में डीजल की मांग पूर्णतया पूरी की जाती है। अप्रैल-जून, 1994 में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर को जितने डीजल की आपूर्ति की गई थी, अप्रैल-जून, 1995 में इसमें क्रमशः 17.2 प्रतिशत, 0.5, 8.8 प्रतिशत और 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

Retrenchment of railway employees

407. SHRI JOYANTA ROY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the World Bank has ince advised the Railway Minsitry to retrench about 4 lakh railway employees;

(b) if so, the reasons shown by the World Bank;

(c) whether Government considered the reasons; and

(d) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) to (d) The World Bank in its report on 'India Transport Sector-Long Term Issues' has felt it necessary to reduce the labour force by about 4 lakh employees as it might be difficult for the Railways to sustain this work force in the coming years.

These are only the views of the World Bank and Government has no such proposal under consideration at this stage.

Privatisaiton of Postal Services

408. DR. BAPU KALDATE:
SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the Minister of COMMUNCIATIONS be pleased to state:

(a) whether privatisation of postal services is being considered; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNCIATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) and (b) There is no move to privatise postal services. However, with a view to providing increased postal facilities to public, a scheme of selling postage stamps and stationery on commission basis has been in operation since 1969.